



होर्मुज जलडमरूमध्य से ईरान नहीं वसूलेगा कोई टोल, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, तेल बाजार को राहत

वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को तेल बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि स्ट्रेट आफ होर्मुज (होर्मुज जलडमरूमध्य) से गुजरने वाले सभी जहाजों पर कोई टोल, वीमा शुल्क या अन्य अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करते हुए बताया कि ईरान ने अमेरिका को सूचित किया है कि यह आश्वासन जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। यह घोषणा मध्य पूर्व में हालिया

तनाव के बाद स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से चल रही वार्ताओं के बीच आई है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था फिलहाल लागू है, लेकिन 60 दिनों की सौजफायर या बातचीत की अवधि समाप्त होने के बाद इसका क्या होगा, इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।

अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता चल रही है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरानी सरकार को कोई तरल निधि या नकद राशि हस्तांतरित नहीं की गई है। उन्होंने यह

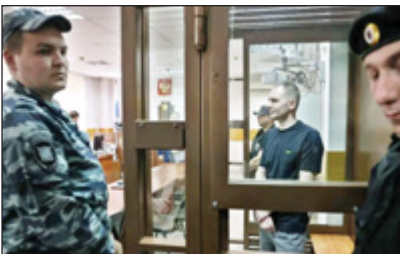
भी बताया कि अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में जमा अरबों डालर को ईरानी संपत्तियों को अब सख्त नियंत्रण वाले नए तंत्र के तहत संभाला जाएगा। प्रशासन की योजना के अनुसार, इन रोके गए फंड्स का उपयोग विशेष रूप से अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे मक्का, गेहूँ और सोयाबीन की खरीद के लिए किया जाएगा, जो सीधे ईरानी जनता के लिए होंगे। ट्रंप ने कहा कि हम उनके कुछ पैसों, जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में हैं, अपने किसानों को देगे क्योंकि ईरान में इन खद्यान्नों की बेहद जरूरत है।

इधर ईरान समुद्री शुल्क वसूलने को तैयार दूरी और, ईरान ने बार-बार कहा है कि वह

होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से समुद्री सेवा शुल्क वसूलने की योजना बना रहा है। तैयार इस टोल नहीं, बल्कि नेविगेशन सहायता, सुरक्षा और रखरखाव जैसी प्रशासनिक सेवाओं के बदले लिया जाने वाला शुल्क बताता है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है, इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताया है। मंगलवार को ईरान और ओमान ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि दोनों देश होर्मुज से जुड़ी प्रशासनिक सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे। बयान में दोनों देशों ने इस जलमार्ग पर अपनी संप्रभुता पर जोर दिया है।

न्यूज़ ब्रीफ

रूसी विपक्षी नेता क्रुलोव को झूट फैलाने के आरोप में 7 साल की जेल



मास्को। रूस में प्रमुख विपक्षी पार्टी यालोको के उपा नेता और यूक्रेन युद्ध के मुखर विरोधी मैक्सिम क्रुलोव को बुधवार को रूसी सेना के बारे में झूट फैलाने के आरोप में दोषी ठहराया गया और सात साल की जेल की सजा सुनाई गई। यह फैसला रूस में सार्वजनिक असहमति पर बढ़ती कार्रवाई को दर्शाता है, जहां युद्ध की आलोचना करने वाले स्वयं को लगातार दबाया जा रहा है। 39 वर्षीय क्रुलोव, जो मास्को की नगर विधानसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, को अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2022 में दो पोस्ट करने का आरोप था, जिस वर्ष रूस ने यूक्रेन पर सैन्य अभियान शुरू किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान, क्रुलोव ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि यह फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रूस में सार्वजनिक असहमति अब अवैध हो गई है, और संक्षेप में, यह असहमति पर एक प्रतिबंध है। उन्होंने अभियोजन पक्ष के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि उनके पोस्ट राजनीतिक नफरत से प्रेरित थे। क्रुलोव ने जोर देकर कहा कि उनका पूरा राजनीतिक करियर रूस में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस फैसले से यह साबित हो गया है कि राजनीतिक असहमति को अब नफरत के समान माना जा रहा है, जो रूस के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए विनाशक है। क्रुलोव ने अदालत में अपना अंतिम बयान देते हुए यह संकल्प लिया कि वे युद्ध के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रूस एक दिन एक शांतिपूर्ण देश बनेगा, एक ऐसा देश जिसका पड़ोसी सम्मान करें, न कि डरे, और जहां असहमति व्यवहार करना संभव हो। यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस में नागरिक स्वतंत्रताएं लगातार संकुचित हो रही हैं। अदालत में पेश किए गए दो पोस्ट में से एक में यूक्रेन संघर्ष में हुई मौतों पर संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का जिक्र था, जबकि दूसरे पोस्ट में मार्च 2022 में कीव के पास युवा में हुई घटनाओं का उल्लेख किया गया था।

चीन ने बना दिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर, अब अमेरिका भी पीछे छूट गया

बीजिंग। प्रौद्योगिकी की दुनिया में चीन ने एक बार फिर अपनी धाक जमाई है। सुपरकंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित करते हुए, चीन के लाइनशाइन नामक सुपरकंप्यूटर ने अमेरिका के शीर्ष कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया में नंबर एक का स्थान हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि साल 2017 के बाद पहली बार है जब किसी चीनी कंप्यूटर ने यह गौरव प्राप्त किया है, जो देश की बढ़ती तकनीकी क्षमता का एक स्पष्ट संकेत है और वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में चीन की मजबूत स्थिति को दर्शाता है।

शेनझेन शहर में स्थित नेशनल सुपरकंप्यूटिंग सेंटर में स्थापित यह लाइनशाइन, हाल ही में जारी हुई प्रतिष्ठित टापू500 रैंकिंग में शीर्ष पर आया है। यह रैंकिंग वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटरों को सूचीबद्ध करती है और इसे किसी भी देश की वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जाता है। यह सूची तकनीकी नवाचार और गणना शक्ति के क्षेत्र में देशों की प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करती है, और इसमें शीर्ष पर आना किसी भी राष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है।

एआई की अगली पीढ़ी सालों नहीं महीनों में बदल देगी साइबर सिक्योरिटी का माहौल

वाशिंगटन। इंटरनेट से अलायंस फाइव आइज ने वेतावनी जारी कर कहा है कि आर्टिफिशियल इंटरनेट (एआई) की अगली जेनरेशन सालों के बजाय कुछ ही महीनों में साइबर सिक्योरिटी के माहौल को पूरी तरह बदल सकती है और सरकारों, बिजनेस और कॉर्पोरेट लीडर्स से साइबर रेंजिलिएंस को तुरंत प्रायोरिटी देने की अपील की है। यह वेतावनी फाइव आइज इंटरनेट्स ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल ने संयुक्त बयान में दी। यह काउंसिल आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की इंटरनेट्स और सुरक्षा एजेंसियों का एक समूह है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि यह ट्रंप प्रशासन ने टेक्नोलॉजी कंपनी एन्थ्रोपिक द्वारा विकसित दो एडवांस्ड एआई सिस्टम तक विदेशी नागरिकों की पहुंच को सीमित करने का कदम उठाया। इस महीने की शुरुआत में घोषित यह फैसला अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के बाद लिया गया। किसी खास कंपनी या माडल का नाम लिए बिना फाइव आइज ने वेतावनी दी गई कि फ्रिटियर एआई सिस्टम से मौजूदा इंडस्ट्री की उम्मीदों से कहीं आगे निकलने और आक्रामक व रक्षात्मक, दोनों तरह की साइबर क्षमताओं में बड़े बदलाव लाने की उम्मीद है।

यूक्रेन में भारत की पीसकीपिंग फोर्स लगाने का प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा - मोदी नहीं मानेंगे

वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही उनके प्रशासन के भीतर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की रणनीति पर गंभीर मतभेद सामने आए थे। 23 जून को जारी हुई ट्रंप प्रशासन के कामकाज पर केंद्रित एक नई किताब रिजीम वेंज ने इस आंतरिक बहस का खुलासा किया है। किताब के अनुसार, 30 जनवरी, 2025 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जो ट्रंप के शपथ ग्रहण के महज 10 दिन बाद हुई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन-रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक अमेरिका फर्स्ट शांति योजना का मसौदा तैयार करना था।

बैठक के दौरान, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय या सऊदी अरब के सैनिकों को पीसकीपिंग फोर्स के रूप में तैनात किया जा सकता है। वेंस का तर्क था कि नाटो देशों के सैनिकों को भेजने से रूस इसे सीधे तौर पर उकसावा मान सकता है, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि, ट्रंप ने इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। किताब में लिखा है कि ट्रंप ने हंसते हुए कहा, भारतीय ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो ऐसी चीजों की कीमत नहीं चुकाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अच्छे व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इससे बावजूद भारत इस तरह के अभियान का आर्थिक बोझ नहीं उठाएगा।

इस बैठक में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कोथ केलाग ने एन अमेरिका फर्स्ट प्लान ट्रंप्स हिस्टोरिक पीस डील फार रूस-यूक्रेन वार नामक एक ड्राफ्ट पेश किया था। इस योजना में युद्धविराम का भी प्रस्ताव था, जिसमें अमेरिका रूस के कब्जाए हुए इलाकों को



औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देगा, लेकिन यूक्रेन भी उन्हें बलपूर्वक वापस लेने की कोशिश नहीं करेगा। शांति बनाए रखने के लिए विदेशी सैनिकों की तैनाती का प्रावधान भी इसमें शामिल था। शुरुआत में यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड के सैनिकों का जिक्र था, लेकिन वेंस ने इसे खतरनाक बताया, जिसके बाद भारत और सऊदी अरब के नाम का समर्थन रखा गया था। यह घटना भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि अमेरिका भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है, जिसकी सैन्य क्षमता को यूक्रेन जैसे संकट में शांति स्थापित करने के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। ट्रंप का बयान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता को भी उजागर करता है। भारत नाटो का हिस्सा नहीं है और न ही अमेरिका के हर अभियान में शामिल होने को तैयार है। ट्रंप का स्पष्ट इनकार भारत पर किसी भी तरह का दबाव डालने से बचाता है, जिससे भारत को यूक्रेन में सैनिक भेजने या किसी बड़े आर्थिक बोझ को उठाने की कोई बाध्यता नहीं होगी। ट्रंप का पीएम मोदी के प्रति सकारात्मक रुख दोनों नेताओं के व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत संबंधों को दर्शाता है।

हालांकि, अगर यह काल्पनिक प्रस्ताव भारत के पास आता और वह इसे स्वीकार कर लेता, तो रूस के साथ उसके संबंधों पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ सकता था। रूस भारत को अपने सबसे पुराने और

भरोसेमंद सहयोगियों में से एक मानता है। भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख बनाए रखा है, पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार किया है और सस्ते रूसी तेल को खरीद जारी रखी है। यूक्रेन में भारतीय सैनिकों की तैनाती रूस के लिए पश्चिमी खेमों में भारत का खुलकर शामिल होना माना जाता, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को रूस का समर्थन भी कमजोर पड़ सकता था। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक स्वायत्तता है, और यूक्रेन में सैनिक भेजकर भारत इस सिद्धांत को कमजोर कर देता। रूस के साथ संबंध खराब होने से भारत को कहीं अधिक नुकसान होता, जितना फायदा उसे पश्चिम या यूक्रेन से मिलता। यही कारण है कि भारत इस युद्ध में शांति का पक्षधर रहा है लेकिन कभी किसी पक्ष का हिस्सा नहीं बना। यह स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट के सिद्धांत पर पूरी तरह अडिग है। वह न तो अमेरिकी सैनिक भेजना चाहता है और न ही अमेरिकी करदाताओं का पैसा यूक्रेन में लगाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह दूसरे देशों से यह उम्मीद करता है कि वे स्वयं खर्च उठाएं। भारत इसके लिए कदापि तैयार नहीं होता, और ट्रंप ने इस बात को भली-भांति भांप लिया था। इस किताब के खुलासे से भारत की छवि एक जिम्मेदार लेकिन स्वायत्त शक्ति के रूप में उभरी है, जिसे अमेरिका सम्मान देता है लेकिन उससे मुफ्त में कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं रखता।

कांगो से निकला इबोला फ्रांस पहुंचा, युगांडा में भी नए मामले



पेरिस। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में शुरू हुए इबोला वायरस के प्रकोप ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि महज एक महीने के भीतर कांगो में पुष्ट मामलों की संख्या एक हजार को पार कर गई है, वहीं युगांडा और फ्रांस में भी नए मामले सामने आए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को देश में इबोला का पहला पुष्ट मामला सामने आने की पुष्टि की, बताया गया कि कांगो से लौटे एक डाक्टर में वायरस की पुष्टि हुई है। मंत्रालय के अनुसार, मरीज मंगलवार को पेरिस पहुंचा था और किशासा से एयर फ्रांस की व्यावसायिक उड़ान से आया था। डाक्टर में सिरदर्द के अलावा अन्य लक्षण लगभग नहीं थे, लेकिन उड़ान के दौरान उनकी हालत थोड़ी बिगड़ गई थी। लैंगिंग के तुरंत बाद उन्हें आइसोलेशन में रख लिया गया, और उनकी हालत स्थिर बताई गई है, उनका वायरल लोड भी बहुत कम है। एयरलाइंस ने सभी यात्रियों की सूची स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंप दी है, और संपर्क में आए व्यक्तियों को ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर, युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में कुल 20 इबोला मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 15 कांगो से आए प्रवासी हैं, जबकि पांच स्थानीय संक्रमण के मामले हैं। राहत की बात यह है कि 20 में से 15 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं, जबकि फिलहाल तीन मरीजों का इलाज चल रहा है और दो लोगों की मौत हो चुकी है।

10 साल तक फ्रांसीसी पत्नी को बंधक बनाकर रखा, बेटे ने कराया आजाद

पाकिस्तान में पाकिस्तानी पति निकला हैवान

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक हृदय विदारक मामला सामने आया है, जहां एक पाकिस्तानी शख्स पर अपनी फ्रांसीसी पत्नी सिल्वी यास्मिना (54) और पांच बच्चों को 10 वर्ष से अधिक समय तक घर में कैद करके रखने और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। इस अमानवीय घटना का खुलासा तब हुआ जब यास्मिना के बेटों में से एक किसी तरह भाग निकलने में सफल रहा और पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रांत के दूरस्थ इलाके बारा में स्थित घर पर छापेमारी की। वहां पुलिस को यास्मिना और उनके पांचों बच्चे एक तंग और बेहद जर्जर कमरे में कैद अवस्था में मिले।

अधिकारियों ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों के शरीर पर चोट के निशान थे, जो पति द्वारा की गई क्रूरता की गवाही दे रहे थे। पुलिस से तुरंत यास्मिना और उनके पांचों बच्चों को पेशावर के एक महिला आश्रय गृह में भर्ती कराया है, जहां उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान किया गया। परिवार



अब फ्रांस लौटने की तैयारी कर रहा है ताकि इस भयावह अनुभव से उबर सकें। यास्मिना ने पुलिस से दिए अपने बयान में बताया कि 2014 में आस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आने के बाद उनके पति ने पूरे परिवार को कैद कर लिया था। उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने या संपर्क करने की अनुमति नहीं थी। उनके दो बड़े बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए, जबकि तीन छोटे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए और उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा।

यास्मिना के अनुसार, उनकी शादी 2003 में हुई थी और पाकिस्तान जाने से पहले वे अपने दो बड़े बच्चों के साथ आस्ट्रेलिया में रह रहे थे।

पाकिस्तान पहुंचने के बाद परिवार का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहा, और उन्हें एक तरह से दुनिया से काट दिया गया। पुलिस ने अभी तक पति की पहचान सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन बताया गया है कि वह पाकिस्तानी नागरिक है, जो यास्मिना से मिलने के समय आस्ट्रेलिया में अवैध रूप से रह रहा था। यास्मिना ने पुलिस को दिए बयान में अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, हमें हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। मेरे पति ने पति और पिता होने के नाते हमारी देखभाल नहीं की, बल्कि हमें रोजाना पीटा और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। उसने आगे कहा कि मेरा भविष्य तो बर्बाद हो चुका है।

अगर दूसरे देशों के पास मिसाइलें हैं तो ईरान के पास मिसाइलें होना गलत नहीं: ट्रंप

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा- मिसाइल कार्यक्रम पर समझौता नहीं, नेतन्याहू को झटका

न्यूयार्क

अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बातचीत को बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि जिन मुद्दों को लेकर युद्ध शुरू हुआ था, उन पर आज भी कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है। कुछ मुद्दों पर बातचीत तो हो भी रही है लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को तो बातचीत की लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया है जो नेतन्याहू का बड़ा मकसद था। मसलन सबसे बड़ा विवाद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर है। वहीं अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर दूसरे देशों के पास मिसाइलें हैं तो ईरान के पास भी कुछ मिसाइलें होना गलत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक



युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि तेहरान की मिसाइल क्षमता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इसे खत्म करना उनके प्रमुख मकसद में शामिल है, लेकिन

अब तस्वीर बदल चुकी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने साफ कहा है कि अमेरिका-ईरान समझौते में मिसाइल कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है और यह मुद्दा कभी बातचीत की मेज पर

नहीं था। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी दो टूक कहा कि उनका देश अपने मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। उनका कहना है कि यही मिसाइलें ईरान की सुरक्षा की गारंटी हैं और अगर ये नहीं होंगी तो अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ भी वही करते जो गाजा में हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप भी अब अपने पुराने रुख से पीछे हट रहे हैं। अप्रैल में जहां वाशिंगटन का लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट करना बताया गया था, वहीं अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर दूसरे देशों के पास मिसाइलें हैं तो ईरान के पास भी कुछ मिसाइलें होना गलत नहीं है।

परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा भी अब तक अनुसलझा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण को अनुमति दे और परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी दे। दूसरी तरफ तेहरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण

उद्देश्यों के लिए है। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास अब भी बरकरार है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। अमेरिका इसे खुला और सुरक्षित रखना चाहता है क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। वहीं ईरान बार-बार यह संकेत देता रहा है कि वह इस रणनीतिक मार्ग पर अपना प्रभाव बनाए रखेगा। इस पूरी तस्वीर में इजराइल सबसे बड़ी बाधा है। अमेरिका क्षेत्रीय संघर्ष खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल अब भी दक्षिणी लेबनान से सेना हटाने को तैयार नहीं दिख रहा। वह हिज्बुल्लाह के पूरी तरह निःशस्त्रीकरण को अपनी शर्त बना चुका है यानी वाशिंगटन और तेल अवीव को प्रार्थमिकताओं में भी अंतर दिखाई दे रहा है। बता दें स्विट्जरलैंड में अगले 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते की कोशिश होगी, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि न मिसाइल मुद्दे पर सहमति बनी है, न परमाणु विवाद सुलझा है, न होर्मुज को लेकर भरोसा कायम हुआ है।